

मुख्यमंत्री ने कॉनक्लेव को राज्य के व्यापार-अनुकूल बदलावों की जानकारी दी

राइजिंग राजस्थान समिट के तहत आयोजित इस कॉनक्लेव में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वैस्टमेंट समिट 2024 के तहत नई दिल्ली में आयोजित कॉनक्लेव में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। नई दिल्ली में निवेशकों की बैठक के बाद राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संग आज एक कॉनक्लेव का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में मौजूद व्यवसाय व निवेश के बारे में बताया और उन्हें प्रदेश में कारोबार बढ़ाने और नए निवेश करने का न्यौता दिया।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर पर 50 से अधिक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य के व्यापारिक परिदृश्य, निवेश के नए अवसरों और

कॉनक्लेव में भाग लेने वालों में प्रमुख थे, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉनकोर, एन.टी.पी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, इण्डियन ऑयल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, आई.टी.डी.सी., फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, डी.आर.डी.ओ. आदि।

राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख व्यापार-अनुकूल बदलावों की जानकारी दी। इस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सी.पी.एस.ई.) कॉनक्लेव में भाग लेने वाले सार्वजनिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दूसरे राज्यों से तुलना अपनी कमी छुपाने का प्रयास’

जयपुर, 1 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बढ़ते लॉबित जांच रिपोर्ट मामले में कहा, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि वहां भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, दूसरे राज्यों से तुलना कर राज्य सरकार की ओर से अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी यदि इस प्रकार अनुचित तुलना करने के बजाए व्यवस्था सुधार पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही अदालत ने

हाई कोर्ट ने एफ.एस.एल. में लम्बित जांच रिपोर्ट के मुद्दे पर राज्य सरकार को फटकार लगाई।

मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि एफ.एस.एल. को संसाधन उपलब्ध कराने के राज्य सरकार की ओर से किए गए बजट आवंटन को लेकर क्या किया गया है और मुख्य सचिव यह भी बताएं कि वे इस प्रकरण में न्यायिक अधिकारियों में चल रहे आरोपों को सांकेतिक तौर पर मुआवजा देने के लिए सहमत हैं या नहीं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपिठ ने यह आदेश अर्जुन नरवाला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एफ.डी.एस. और डी.जी.पी. अदालत में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने इज़राइल पर हमला किया

सूत्रों के अनुसार ईरान ने देर रात दस बजे इज़राइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागीं

- हमले के बाद ईरान ने कहा कि यह नसरल्लाह की शहादत का बदला है, यह तो अभी शुरूआत है।
- इधर इज़राइल ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया और अपने लोगों को बम शैल्टर्स में जाने की हिदायत दी है।
- इज़राइल पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्यूरिटी टीम के साथ बैठक की।

नयी दिल्ली, 01 अक्टूबर। ईरान ने इज़राइल पर मंगलवार की देर रात 10 बजे हमला कर दिया और 180 से ज्यादा मिसाइलें दागीं। इज़राइली सरकार ने अपने नागरिकों से बम शैल्टर में जाने को कहा है। पूरे देश में सायरन बज रहे हैं। अमेरिका ने कुछ घंटे पहले हमले का दावा किया था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि नसरल्लाह की शहादत का यह पहला बदला है। यह तो अभी शुरूआत है।

उधर, इज़रायल डिफेंस फोर्स (आई.डी.एफ.) के एक अधिकारी ने कहा, इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। वह खतरों का पता लगा रहा है और जहां जरूरत है वहां उन्हें रोक रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि वे इज़राइल से बदला लेने की शुरूआत है।

हालांकि, इज़रायल का कहना है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है और नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा है कि हम सब जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इज़रायल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध का करारा जवाब मिलेगा। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले

में इज़रायल में भारी नुकसान हुआ है। उधर आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि ईरान के हमले में लगभग 1 करोड़ लोग निशाने पर थे। ईरान की ओर से इज़राइल पर रिकेट दागे जाने के कारण सभी इज़राइली नागरिक बम आश्रय स्थलों में हैं। बाइडन ने इमरजेंसी बैठक की। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान के इज़राइल पर हमले की चर्चा की गई। साथ ही इज़राइल को इस हमले से कैसे बचाया जाए और इज़राइल में फंसे अमेरिकियों को मदद की क्या तैयारी है, इस पर बात हुई।

जानकारी के मुताबिक, ईरानी प्रोजेक्टाइल के निशाने पर 10 मिलियन नागरिक हैं। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शैल्टर में गए हैं और वहां से अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। पूरे इज़रायल में सायरन बज रहे हैं। इज़रायल की ओर जाते समय जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में ईरानी मिसाइलों को रोकना गया है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि ईरान को, इज़रायल पर सीधे हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, मैंने अपने इज़रायली समकक्ष के साथ ईरान को भुगतने वाले गंभीर परिणामों पर चर्चा की है। इज़रायल की ओर ईरानी मिसाइलों की पहली लहर के बाद इराक ने हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है।

कई दशकों के इंतज़ार के बाद शिगेरु जापान के प्र.मंत्री बने

हालांकि, शिगेरु की वर्षों की महत्वाकांक्षा अब पूरी हुई, पर, प्र. मंत्री के रूप में उनकी यात्रा काफी कठिन नज़र आ रही है

अंजन रॉय-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। ईशोबा शिगेरु ऐसे समय पर जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जब जापान एक तरह से दोराह पर खड़ा है।

शिगेरु लंबे समय से हाशिए पर थे। नेता के रूप में उभरने के उनके प्रयास कई बार नाकाम हुए। लेकिन, जब पिछले प्रधानमंत्री को बदनामी की स्थिति में पद छोड़ना पड़ा, जब जाकर ही शिगेरु प्रधानमंत्री पद पर दावा कर पाए।

अब उन्हें वो पद मिल गया है, जिसे पाने की लालसा उन्हें लंबे समय से थी, लेकिन उनके लिए यह राह असान नहीं होगी। तीन दशकों से जापान पिछड़ रहा है। 'लॉस्ट डेकेड्स' के नाम से पुकारे जाने वाले और 1990 से शुरू हुए इन दशकों में जापान गिरते दामों का सामना कर रहा था। अर्थव्यवस्था में कोई प्रोथ दिखाई नहीं दी तथा आमतौर से, जिसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जापान की सभी मुश्किलों की जड़ है, उसकी घटती जनसंख्या। घटती आबादी के कारण गांव खाली हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए क्लासें लगाई जाएं, फैक्टोरियां बंद हो रही हैं, क्योंकि मजदूर नहीं हैं।

इस घटती जनसंख्या का एक पहलू यह भी है कि 30 प्रतिशत जनसंख्या 60 साल से अधिक आयु की है, अतः उनकी पैन्शन व स्वास्थ्य संबंधी अवश्यकता को पूरा करने के लिए देश की आय का बड़ा अंश लग जाता है।

समस्या और गंभीर इसलिये हो जाती है, क्योंकि जापान की बहुत सख्त नीति है, बाहरी लोगों को जापान आकर बसने देने के मामले में। संकट का एक समाधान हो सकता था, अगर महिलाओं की औद्योगिक व अन्य व्यावसायिक कामों में हिस्सेदारी बढ़ायी जाये, पर, यह भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जापानी समाज का एक बड़ा धड़ मानता है कि देश की गिरती जनसंख्या बढ़ाने में महिलाओं की सक्रिय भूमिका होनी चाहिये, अतः उन पर और काम न लादा जाये।

तिरुपति लड्डू विवाद की सुनवाई 3 अक्टूबर को

जाल खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू प्रकरण में आंध्र प्रदेश की एस.आई.टी. जांच पर रोक लगा दी है और अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। यह विवाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने कहा था कि तिरुपति मंदिर प्रसाद के लड्डूओं में पशु चर्बी पाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की एस.आई.टी. जांच पर भी रोक लगा दी है।

रेड्डी ने मुख्यमंत्री के इस आरोप का खंडन किया था और उनके ऊपर 'भागवान के नाम पर राजनीति' करने का आरोप लगाया था। रेड्डी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई मिलावट नहीं की गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को आदतन झूठ बोलने वाला बताया। नायडू ने गुजरात की एक निजी लैब की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा था कि लड्डूओं के घों में पशु चर्बी मिली हुई थी।

पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार

वांगचुक ने पुलिस स्टेशन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया

डॉ. सतीश मिश्रा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। विपक्ष ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली सीमा पर साथियों सहित गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। वांगचुक लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के स्टेटस की मांग के लिए दिल्ली मार्च पर आए हैं। वांगचुक ने पुलिस थाने में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है।

वांगचुक के एक सितम्बर को लेह से 'दिल्ली चलो' पदयात्रा शुरू की थी। इस पदयात्रा को लेह अपेक्स बाडी (एल.ए.बी.) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस का समर्थन प्राप्त है। ये समूह लद्दाख को राज्य बनाए जाने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करने, लोक सेवा आयोग, लेह व कारगिल के लिए पृथक लोकसभा सीट देने की मांग कर रहे हैं, पर जैसे ही वांगचुक का काफिला 30

वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा इसके रोलेशियर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक सितम्बर को 'दिल्ली चलो पदयात्रा' शुरू की थी और मंगलवार को वे दिल्ली पहुंचे।

वांगचुक ने खुद डिटेल किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। समूचे विपक्ष ने इस कृत्य के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है।

वांगचुक अपनी मांगों के लिए लद्दाख में इसी वर्ष मार्च में 21 दिन का अनशन कर चुके हैं।

सितम्बर को दिल्ली पहुंचा, उन्हें सीमा पर ही रोक लिया गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विपक्षी नेताओं ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया। डिटेल किए जाने से पहले वांगचुक ने दिल्ली बॉर्डर से जहां पुलिस ने उनकी बसों को रोका था, की तस्वीरें शेयर की थीं और लिखा था, ऐसा लगता है, हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, बल्कि हमें हिरासत में लिया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने कानून और व्यवस्था के प्रति चिंता जताते हुए प्रदर्शनकारियों के दिल्ली के करीब आने से पहले ही सेंट्रल दिल्ली और आस पास के क्षेत्र में 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी थी। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू कर दी गई है जिसके तहत 6 दिन तक विरोध प्रदर्शनों पर रोक है।

विपक्षी नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने वांगचुक एवं लद्दाखी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को अस्वीकार्य करार दिया। गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि वे पर्यावरण व संवैधानिक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। सोनम वांगचुक लद्दाखी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली सीमा पर लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। मोदी जी, किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटगा और आपका अहंकार भी। आपको लद्दाख को आवाज सुननी होगी।

आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा कर क्या रहे हैं। दिल्ली में भाजपा गैंगस्टर्स को पूर्ण सुरक्षा देती है, पर सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश को प्यार करते हैं, के साथ आतंकी जैसा व्यवहार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारी अनुमति के बिना बुलडोज़र कार्यवाही नहीं होगी'

जाल खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यों द्वारा दण्डात्मक उपाय के रूप में बुलडोज़रों से मकानों को गिराये जाने के खिलाफ दिशानिर्देश तैयार करने के आदेश जारी कर दिये।

सुप्रीम कोर्ट ने उपराधियों के मकान तोड़ने की बुलडोज़र कार्यवाही पर लगाए गए स्टे की अवधि बढ़ा दी है।

अदालत ने ऐसी कई याचिकाओं की सुनवाई की, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में, सम्पत्तियां, जिनमें अपराधों के आरोपियों की सम्पत्तियां भी शामिल हैं, ध्वस्त की जा रही हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई तथा के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने 17 सितम्बर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गोगुंदा में बारह दिन में 8 लोगों की जान ली आदमखोर पैंथर ने

मंगलवार को पैंथर ने गोगुंदा में अपने घर में पशुओं के बाड़े में काम कर रही महिला को अपना शिकार बनाया

शुरू कर दी है। पिछले 12 दिनों में 8 लोगों को अपना शिकार बनाने वाले पैंथर को पकड़ने में नाकाम रहे प्रशासन से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की।

मंगलवार को मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। इनके अलावा, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल वही पर डेरा डाले हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह आठ बजे केलवों का खेड़ा गांव में महिला कमला कुंवर अपने घर के आंगन में काम कर रही थीं। पैंथर ने उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर परिवार के दूसरे लोग बाहर भागे तो पैंथर उसके शव को छोड़कर भाग गया। पैंथर महिला को घर से 100 मीटर दूर तक घसीट कर ले

पैंथर महिला पर हमला कर उसे घसीट कर ले गया। महिला की चीख सुनकर जब परिजन दौड़े तो पैंथर भाग गया, पर, तब तक महिला मर चुकी थी।

वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक ने पैंथर को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। पूरे जंगल में पैंथर की तलाश की जा रही है।

पैंथर को पकड़ने में वन विभाग और प्रशासन की नाकामी से गुस्सा ग्रामीणों ने हाइवे जाम करने की कोशिश की।

मौत हो गई। वन विभाग की एक दर्जन से ज्यादा टीमों के केलवों का खेड़ा के जंगल में पैंथर को गोली मारने की तैयारी में जुटी है। टीम के साथ डोल बजाने वाले भी हैं, जो जंगल में डोल बजाकर आदमखोर पैंथर को दौड़ाएंगे। वन विभाग ने कहा

200 भारतीय शिक्षक फ्रेंच स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाएंगे

डॉ. सतीश मिश्रा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। भारत में फ्रांस के दूतावास ने इन्स्टीट्यूट फ्रांसे इंडिया (आई.एफ.आई.) तथा फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ नैशनल एजुकेशन के सहयोग से 206 इंडियन लैंग्वेज असिस्टेंट्स के फ्रांस जाने की घोषणा

ये शिक्षक 2024-25 शैक्षणिक सत्र में अक्टूबर से अप्रैल तक फ्रांस में रहेंगे और वहाँ के अंग्रेजी शिक्षकों की मदद करेंगे।

की है। ये लोग शैक्षिक सत्र 2024-25 में विभिन्न प्राइमरी एवं सैकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने फ्रांस जायेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट्स प्रोग्राम के हिस्से के रूप में, ये लोग वहाँ अक्टूबर से अप्रैल तक रहेंगे तथा फ्रांस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)